

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 559
20 जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न
राशन कार्डों को आधार के साथ जोड़ना

559. श्रीमती अपरूपा पोद्दार:

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित:

ओ रमेश बिन्द:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पारदर्शिता पोर्टलों पर उपलब्ध राशन कार्डों की संख्या/प्रतिशतता कितनी है;
- (ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लिंक किए गए आधार कार्डों का प्रतिशत कितना है;
- (ग) शेष राशन कार्डों को कब तक आधार से लिंक किए जाने की संभावना है; और
- (घ) क्या सरकार ने सार्वजनिक और वितरण प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है और सभी 19.5 करोड़ (लगभग) राशन कार्ड संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पारदर्शिता पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(ख): राशन कार्ड में आधार सीडिंग की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(ग): एनएफएसए के तहत कुल 19.5 करोड़ राशन कार्डों में से 99 प्रतिशत को पहले ही आधार संख्या (अर्थात परिवार के कम से कम एक सदस्य) के साथ जोड़ा जा चुका है। शेष राशन कार्डों की आधार सीडिंग पूरी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 30.09.2022 तक का समय दिया गया है।

(घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का प्रभावी कार्यान्वयन करने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने एक योजना - "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण" लागू की है। इस योजना के तहत, राशन कार्ड/लाभार्थी और अन्य डेटाबेस का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन आबंटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां चलाई गई थीं। इसके अतिरिक्त उचित दर दुकानों (एफपीएस) का स्वचालन भी किया गया है, जिसमें लाभार्थियों के प्रमाणीकरण और लेन-देन के आंकड़ों के इलेक्ट्रॉनिक कैचरिंग के लिए एफपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण की स्थापना करना शामिल है। देश में कुल 5.33 लाख उचित दर दुकानों में से लगभग 5.32 लाख उचित दर दुकानों को अब तक स्वचालित किया जा चुका है।

लोक सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 559 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध राशन कार्ड में आधार सीडिंग की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	राशन कार्डों का % सीडिंग
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	100%
2	आंध्र प्रदेश	100%
3	अरुणाचल प्रदेश	85%
4	असम	93%
5	बिहार	100%
6	चंडीगढ़	100%
7	छत्तीसगढ़	100%
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	100%
9	दिल्ली	100%
10	गोवा	100%
11	गुजरात	100%
12	हरियाणा	100%
13	हिमाचल प्रदेश	100%
14	जम्मू और कश्मीर	100%
15	झारखंड	98%
16	कर्नाटक	100%
17	केरल	100%
18	लद्दाख	99%
19	लक्षद्वीप	100%
20	मध्य प्रदेश	100%
21	महाराष्ट्र	100%
22	मणिपुर	99%
23	मेघालय	38%
24	मिजोरम	98%
25	नागालैंड	92%
26	ओडिशा	99%
27	पुदुच्चेरी	97.4%
28	पंजाब	100%
29	राजस्थान	100%
30	सिक्किम	100%
31	तमिलनाडु	100%
32	तेलंगाना	100%
33	त्रिपुरा	100%
34	उत्तराखंड	100%
35	उत्तर प्रदेश	100%
36	पश्चिम बंगाल	95%
	राष्ट्रीय सारांश	99.1%